RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 248
दि. 08.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सड़कों पर भय बनते आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा—लोग कब तक जान जोखिम में डालकर जिएंगे

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में सड़कों पर बढ़ते आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि यह मुद्दा अब केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि सीधे-सीधे आम नागरिकों की जान और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सार्वजनिक संकट बन चुका है। अदालत ने सवाल उठाया कि आखिर लोग कब तक आवारा कुत्तों और पशुओं के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में डर और खतरे के साये में रहने को मजबूर होंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि देश में केवल कुत्तों के काटने की घटनाएं ही चिंता का विषय नहीं हैं, बल्कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अदालत ने माना कि यह समस्या अब शहरी अव्यवस्था का प्रतीक बन चुकी है और इसे नजरअंदाज करना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। अदालत की टिप्पणी उस समय और भी गंभीर हो गई जब जस्टिस संदीप मेहता ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि पिछले महज 20 दिनों में राजस्थान हाई कोर्ट के दो जज आवारा जानवरों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इनमें से एक जज को रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। इस उदाहरण के जरिए पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह खतरा किसी एक वर्ग या आम नागरिक तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के सदस्य भी इससे सुरक्षित नहीं हैं। अदालत ने कहा कि जब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसे हल्के में लेना अपराध के समान है।

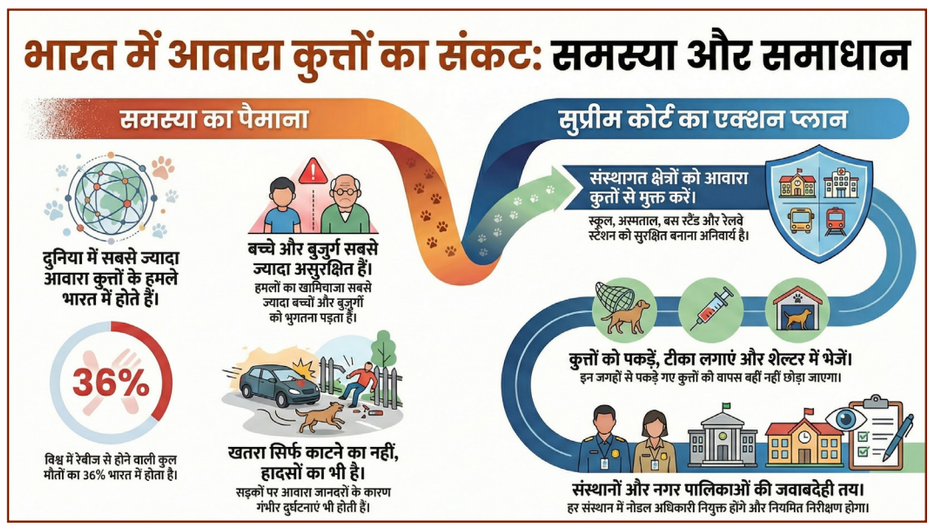

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी तीखा सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि नियम, दिशा-निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। उन्हें सख्ती से जमीन पर लागू करना नगर निकायों की जिम्मेदारी है। जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी की कि सुबह के समय कौन सा कुत्ता किस मिजाज में होगा, यह कोई नहीं जान सकता और आम नागरिक हर दिन इसी अनिश्चितता के साथ घर से बाहर निकलता है। कोर्ट ने साफ किया कि अब इस तरह की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान केवल उन्हें पकड़कर हटाने से संभव नहीं है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए वैज्ञानिक मॉडल CSVR का हवाला दिया, जिसमें कुत्तों को पकड़ना, उनकी नसबंदी करना, टीकाकरण करना और फिर उन्हें वापस छोड़ना शामिल है। सिब्बल ने कहा कि यह प्रक्रिया दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती है और इससे कुत्तों की आबादी नियंत्रित होती है, साथ ही काटने की घटनाओं में भी कमी आती है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी समाधान में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसका उद्देश्य किसी कानून या नियम में दखल देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि संस्थागत क्षेत्रों को आवारा कुत्तों से मुक्त रखा जाए। अदालत ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में बच्चों, मरीजों और आम लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। जस्टिस नाथ ने इस संदर्भ में कहा कि इलाज से बेहतर है परहेज, यानी दुर्घटना या हमले के बाद मुआवजे और इलाज की बात करने से बेहतर है कि ऐसी घटनाएं हों ही नहीं।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अब तक अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों के रवैये पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों ने या तो जवाब ही नहीं दिया या फिर बेहद निराशाजनक और औपचारिक हलफनामा दाखिल किया है, जिससे उनकी गंभीरता पर सवाल उठते हैं। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित राज्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मामले में नियुक्त न्याय मित्र गौरव अग्रवाल ने अदालत को बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आवारा जानवरों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एक SOP तैयार की है और लगभग 1,400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। हालांकि, NHAI का यह भी कहना है कि इन सड़कों के रखरखाव और सुरक्षा उपायों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर आवारा जानवरों की आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी बाड़बंदी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान विभिन्न वकीलों ने अदालत को बताया कि देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों में मासूम बच्चों और वयस्कों की जान जा चुकी है। इन घटनाओं के कारण समाज में भय का माहौल है और लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन तथ्यों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में नागरिकों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता।

अदालत ने दोहराया कि यह मामला केवल पशु अधिकार और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। सुप्रीम कोर्ट अब राज्यों के जवाब, नगर निकायों की तैयारियों और जमीनी हकीकत की समीक्षा करेगा ताकि आवारा जानवरों के प्रबंधन के लिए एक ठोस, व्यावहारिक और प्रभावी कार्ययोजना बनाई जा सके। कोर्ट का स्पष्ट संदेश है कि सड़कों पर लोगों की जान से खिलवाड़ अब और नहीं चलेगा, और इस समस्या का समाधान टालने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

पांच राज्यों में चुनावी शंखनाद से पहले भाजपा का बड़ा सियासी प्लान, शीर्ष नेताओं के दौरों से बनेगा माहौल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से पूरी ताकत झोंकने का फैसला कर लिया है। चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले ही पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और राजनीतिक संदेश तीनों मोर्चों पर भाजपा की मौजूदगी साफ और प्रभावी दिखे। इसी उद्देश्य से पार्टी ने अपने शीर्ष केंद्रीय नेताओं के रणनीतिक दौरों की विस्तृत योजना तैयार की है, जिसे सामान्य दौरे नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा नेतृत्व का आकलन है कि चुनाव की घोषणा से पहले किया गया सघन संपर्क अभियान न केवल कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरता है, बल्कि आम मतदाता के मन में पार्टी की सक्रियता और गंभीरता का भरोसा भी मजबूत करता है। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रमों को इस तरह तय किया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य

तक राजनीतिक लय बनी रहे और अभियान की रफ्तार कहीं भी धीमी न पड़े। पश्चिम बंगाल इस पूरी रणनीति का सबसे अहम केंद्र बनकर उभरा है। पार्टी ने यहां चुनाव से पहले चार बड़े केंद्रीय नेताओं के लगभग 20 कार्यक्रम तय किए हैं। इन दौरों में जनसभाएं, संगठनात्मक बैठकें, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद और सामाजिक वर्गों के साथ लक्षित संपर्क शामिल हैं। भाजपा का मानना है कि बंगाल में सत्ता विरोधी भावनाएं मौजूद हैं, जिन्हें सही दिशा और तीव्रता देने की जरूरत है। इसी कारण संगठनात्मक फेरबदल और आंतरिक बदलावों के बावजूद पार्टी ने बंगाल की चुनावी तैयारी में कोई ढील नहीं दी है।

गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल की रणनीति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी का फोकस केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन की जमीनी मजबूती, स्थानीय नेतृत्व को धार देना और विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करना भी इस अभियान का हिस्सा है। कई कार्यक्रमों को सरकारी योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़कर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि केंद्र की नीतियां सीधे राज्य की जनता के हित से जुड़ी हैं।

दूसरी ओर, दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी अलग-अलग रणनीतिक खाके तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में, जहां भाजपा का विस्तार अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण रहा है, वहां पार्टी नेतृत्व करीब 10-10 बड़े दौरों की योजना बना रहा है। इन राज्यों में जोर वैचारिक विस्तार, क्षेत्रीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख और स्थानीय सहयोगियों के साथ संतुलन बनाने पर रहेगा। पार्टी का उद्देश्य यहां दीर्घकालिक राजनीतिक आधार तैयार करना है, ताकि भविष्य में भाजपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित किया जा सके।

असम में भाजपा की रणनीति अपेक्षाकृत व्यावहारिक और गठबंधन-केंद्रित है। यहां पार्टी न केवल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, बल्कि क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल और सीटों के रणनीतिक बंटवारे पर भी काम कर रही है। इसके साथ ही, बांग्लादेश से जुड़ी समसामयिक घटनाओं और सीमावर्ती मुद्दों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाकर भाजपा अपने परंपरागत मतदाता आधार को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है, वहां पार्टी का मुख्य लक्ष्य सत्ता विरोधी माहौल को धार देना और खुद को एक आक्रामक, विश्वसनीय और संगठित विपक्ष के रूप में पेश करना है।

प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने के प्रस्ताव पर संसद में मंथन, नेता प्रतिपक्ष को लेकर उठा बड़ा संवैधानिक सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद एक महीने तक जमानत न मिलने की स्थिति में पद से हटाने से जुड़े प्रस्तावित कानून ने संसद की संयुक्त समिति की बैठक में तीखी और गहन बहस को जन्म दिया। बुधवार को हुई बैठक में इस बात पर खास तौर पर सवाल उठे कि यदि ऐसा कानून अस्तित्व में आता है, तो क्या इसका दायरा केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक सीमित रहेगा या फिर इसमें नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक और वैधानिक पद भी शामिल होंगे। समिति के कई सदस्यों ने इस मुद्दे को लोकतंत्र की बुनियादी संरचना से जुड़ा हुआ बताते हुए स्पष्टता की मांग की। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक की समीक्षा कर रही है। बैठक में विधि आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति जी.एस. बाजपेयी और नालसार विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीकृष्ण देव राव ने समिति के समक्ष अपने कानूनी और संवैधानिक विचार रखे। विशेषज्ञों ने प्रस्तावित कानूनों के प्रभाव, उनकी संवैधानिक वैधता और लोकतांत्रिक संतुलन पर पड़ने वाले असर को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने यह सवाल विशेष रूप से उठाया कि यदि नेता प्रतिपक्ष किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और एक महीने के भीतर जमानत नहीं ले पाता, तो क्या उसे भी उसके पद से हटाया जाएगा। यह सवाल इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक वैधानिक पद है, जिसकी भूमिका संसदीय लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष के संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बिंदु पर समिति में लंबी चर्चा हुई, हालांकि किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और अध्ययन की जरूरत बताई गई। बैठक के दौरान विपक्ष के एक सदस्य ने यह मांग भी रखी कि संयुक्त संसदीय समिति का हिस्सा नहीं होने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इन विधेयकों पर अपनी राय रखने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि व्यापक राजनीतिक सहमति बन सके। हालांकि, समिति के कुछ अन्य सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि समिति पहले से ही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गठित है और हर दल को इसमें शामिल होने का अवसर दिया गया था। 31 सदस्यीय इस संयुक्त समिति की संरचना को लेकर भी राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं। विपक्ष की ओर से समिति में केवल एनसीपी की सुप्रिया सुले, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और वाईएसआरसीपी के एस. निरंजन रेड्डी शामिल हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना-यूबीटी और आम आदमी पार्टी जैसे प्रमुख विपक्षी दलों ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इन दलों का आरोप है कि प्रस्तावित विधेयक उस मूल कानूनी सिद्धांत के खिलाफ हैं, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। बैठक के बाद समिति अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि समिति के समक्ष पेश हुए सभी विशेषज्ञों से लिखित सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं, ताकि विधेयकों पर गहन और तथ्यपरक विचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि समिति किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संवैधानिक, कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं की गंभीरता से समीक्षा करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 17 दिसंबर को हुई बैठक में भी संसदीय पैनल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने से जुड़े विधेयकों पर सबूतों के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा था। समिति ने यह भी पूछा था कि इस तरह के कानून की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है और क्या दुनिया के किसी अन्य लोकतांत्रिक देश में ऐसे कानूनों के उदाहरण मौजूद हैं।

अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में शोक और आक्रोश, सात दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित

(जीएनएस)। कराकस। वेनेजुएला में हालात एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। कराकस में कथित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान हुई मौतों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने पूरे देश में सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह शोक उन नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों के सम्मान में है, जिन्होंने देश की संप्रभुता और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई।

सरकारी टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि वेनेजुएला में कोई आंतरिक युद्ध नहीं चल रहा था, इसके बावजूद उस पर बाहरी हमला किया गया। उन्होंने इसे देश की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय पर हमला बताते हुए कहा कि वेनेजुएला की जनता और सरकार ऐसे दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगी। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश का शासन पूरी तरह वेनेजुएला की सरकार के हाथ में है और किसी भी विदेशी ताकत को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

रोड्रिगेज ने अमेरिका की हिरासत में रखे गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की तत्काल वापसी की मांग करते हुए कहा कि यह पूरा घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय कानूनों और कूटनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वेनेजुएला को किसी बाहरी एजेंट या ताकत द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता और देश की जनता ही अपने भविष्य का फैसला करेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, मादुरो को पकड़ने के उद्देश्य से की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में कम से कम 24 वेनेजुएलाई सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि हुई है। इन मौतों ने देशभर में गहरा शोक और गुस्सा पैदा कर दिया है। राजधानी कराकस समेत कई शहरों में सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुका दिए गए हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है।

इस बीच वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारेक विलियम साब ने इस कार्रवाई को युद्ध अपराध करार देते हुए इसकी अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी संप्रभु देश में इस तरह की सैन्य कार्रवाई न केवल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह मानवाधिकारों पर भी सीधा हमला है। साब ने संकेत दिया कि वेनेजुएला इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा और दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

देश में घोषित सात दिन के राष्ट्रीय शोक के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह समय केवल शोक मनाने का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की रक्षा के संकल्प को और मजबूत करने का भी है। वेनेजुएला की सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में इस घटनाक्रम को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।

नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक से थमी कार्रवाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। पहलगाम आतंकी हमले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी उनकी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने यह आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब मांगा है। इस फैसले के बाद फिलहाल नेहा सिंह राठौर की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद नेहा सिंह राठौर की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इन पोस्ट को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उनकी टिप्पणियों से दो समुदायों के बीच नफरत फैलने की आशंका पैदा हुई और इससे देश की राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है। पुलिस का यह भी कहना था कि संवेदनशील समय में इस तरह के बयान देश की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और उन्हें बिना ठोस आधार के निशाना बनाया जा रहा है।

संपादकीय

पंजाब में बढ़ते अपराध

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब में सरेआम की जा रही लक्षित हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुस्साहसी हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम देकर साफ निकल जाते हैं। यह विडंबना ही है कि पंजाब में नये साल की शुरुआत दिनदहाड़े हुई हत्याओं की एक श्रृंखला के साथ हुई है। अब चाहे लुधियाना जिले में एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की निर्मम हत्या हो या अमृतसर के मैरिज रिसॉर्ट में एक विधायक के करीबी सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या, इनसे पता चलता है कि पंजाब के अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया। निश्चित रूप से ये घटनाएं पंजाब में गंभीर चुनौती बनती एक जटिल समस्या की ओर इशारा करती हैं। इस चिंताजनक होती स्थिति की वजह लगातार अपराधी गिरोहों के नेटवर्क का मजबूत होना, घातक हथियारों की सहज उपलब्धता और पुलिस बल पर लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाए रहते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों के लिये मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते रहते हैं। वहीं सरकार इस संकट को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में छोड़ा गया बताते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि इन बयानबाजियों से नागरिकों की असुरक्षा कम नहीं होती है। वहीं पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की दलील होती है कि पंजाब में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन राज्य में बढ़ते अपराधों के संकट को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब हत्याएं राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होती हैं तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य के पुलिस महानिदेशक की दलील है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिये हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ भेजकर सीमांत राज्य पंजाब के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़े हुए है। निश्चय ही यह बात इस सीमावर्ती राज्य के लिये गंभीर चिंता का विषय है। इसमें दो राय नहीं कि पंजाब के डीजीपी का पाक से अपराधियों को प्रश्रय देने वाला बयान चिंता बढ़ाने वाला है। खासकर उस राज्य के लिये, जिसने एक दशक तक उग्रवाद का सामना किया हो। लेकिन पंजाब के अपराध संकट के लिये केवल बाहरी कारकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह पुलिस विभाग की शिथिलता व खुफिया तंत्र की नाकामी के साथ सामाजिक विद्रूपताओं से भी उपजा संकट है। निस्संदेह, राज्य में अधिक बेरोजगारी है। बंदूक संस्कृति का महिमामंडन भी गंभीर चुनौती है। वहीं दूसरी ओर युवाओं में रातों-रात धनवान बनने का लालच भी स्थानीय व क्षेत्रीय गिरोहों के पनपने की गंभीर वजह है। इसके अलावा पुलिस विभाग की संरचना की भी कुछ विसंगतियां सामने आती हैं। मसलन पुलिस व्यवस्था में उच्च अधिकारियों की तो अधिकता है मगर फील्ड स्टाफ पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा है। इसके अलावा पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के भी आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस, हासिल कुछ सफलताओं के बावजूद जनता का विश्वास जीतने के लिये संघर्ष कर रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर राज्य सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव लाकर धरातल पर गंभीर प्रयास करने होंगे। मौजूदा हालात में बहुआयामी रणनीति बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। इसके अंतर्गत पुलिस सुधार भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है, ताकि हाइटैक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण में केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर तालमेल करने की भी जरूरत है। इसके अलावा बंदूकों पर लगाम लगाने के लिये कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता होगी। राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कौशल विकास में व्यापक निवेश करने तथा भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयास योजनाबद्ध ढंग से करने होंगे। ऐसे राज्य में जो एक दशक तक चरमपंथ की त्रासदी झेल चुका हो, अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम वक्त की मांग है। राज्य के सत्ताधीशों को चाहिए कि पंजाब द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को गैंगस्टरों, ड्रग माफिया और आतंकवादियों के घातक गठजोड़ का शिकार कदापि नहीं होने दें।

मादुरो पर अमेरिकी हमले का फेंटानिल एंगल

"रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, '2024 में ड्रग ओवरडोज से 1,07,543 अमेरिकियों की मौत हुई, जिसमें फेंटेनाइल की वजह से 76,000 से ज़्यादा मौतें हुईं। 2025 तक अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों की दर दोगुनी से ज़्यादा हो गई, इसका बड़ा कारण फेंटानिल की सप्लाई में बढ़ोतरी थी।'

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका में नशीले कारोबार का सूत्रधार होने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसके मूल में अमेरिकी युवाओं की रगों में जहर घोलने वाले उच्च तीव्रता के फेंटानिल की तस्करी शामिल रही है। कुछ जानकार बताते हैं कि फेंटानिल ही अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को फर्स्ट लेडी समेत हिरासत में लेने की सबसे बड़ी वजह रही है। जबकि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी लिप्सा किसी से छिपी नहीं है।

दरअसल, फेंटानिल, धीरे-धीरे दुनियाभर में सुर्खियों में नजर आ रहा है। अटलांटिक के इस पार यह दवा उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन अमेरिका के अनुभवों को देखते हुए यह स्थिति बदलने वाली है। फेंटानिल एक ऐसी समस्या है, जो शायद ही कभी हल होगी। यह ड्रग, हेरोइन से सौ गुना अधिक घातक है। इसके लिए गांजे या अफ़ीम की खेती की ज़रूरत नहीं है। लैब में तैयार फेन्टानिल, एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा है, जो मॉर्फिन से 50 गुना अधिक असरदार है। इसे मूल रूप से बेल्जियम के रसायनज्ञ पॉल जैन्सन द्वारा संश्लेषित किया गया था। इस दवा का उपयोग बड़ी सर्जरी के लिए होता रहा है, या फिर कैंसर से होने वाले असहनीय दर्द को कम करने में फेंटानिल उपयोगी है।

भले ही रासायनिक रूप से इसका अफीम से कोई संबंध न हो, मगर यह दवा मॉर्फिन और हेरोइन के समान ओपिओइड रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए इसे 'ओपिओइड' कहा जाता है। हमारे शरीर में ऐसे रसायन निकलते हैं, जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, ये उन गतिविधियों को बूस्ट करते हैं, जैसे खान-पान का स्वाद लेने, या फिर यौन व्यवहार में। शरीर में अच्छा महसूस कराने वाले रसायनों की मात्रा बढ़ने के कारण ही ओपिओइड की लत लोग लगा लेते हैं। मतलब, दर्द निवारण

के लिए निर्मित फेंटानिल, मौज-मस्ती का साधन बन चुका है।

गंभीर चुनौती यह है कि फेंटानिल की लत एक बार लग गई तो उससे छुटकारा मौत के बाद ही मिल पाता है। साल 1960 के दशक से ही फेंटानिल के मूल तत्व में कई बदलाव और सुधार किए गए हैं, जिससे इसके अनेक प्रकार के वेरिएंट तैयार हुए हैं, जिनका शरीर पर अलग-अलग प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, 'कार्फेंटानिल', मॉर्फिन से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। 'कार्फेंटानिल' का उपयोग, उन्मत हाथियों को शांत करने के लिए किया जाता है। हेरोइन और कोकीन जैसी दवाओं के साथ फेंटानिल को मिलाने से इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। केवल दो मिलीग्राम फेंटानिल एक वयस्क के लिए घातक हो सकता है। फेंटानिल अमेरिका के ओपिओइड संकट का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। सही से देखा जाये, तो हाल ही में यह खबर आई कि पिछले आठ महीनों में ब्रिटेन में फेंटानिल के कारण कम से कम 75 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन, अमेरिका में इस दवा के कारण मरने वालों की संख्या के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, '2024 में ड्रग ओवरडोज़ से 1,07,543 अमेरिकियों की मौत हुई, जिसमें फेंटेनाइल की वजह से 76,000 से ज़्यादा मौतें हुईं। 2025 तक अमेरिका में ड्रग ओवरडोज़ से होने वाली मौतों की दर दोगुनी से ज़्यादा हो गई, इसका बड़ा कारण फेंटानिल की सप्लाई में बढ़ोतरी थी।' डेटा एनालिसिस से पता चलता है, कि फेंटानिल की तस्करी में शामिल लोगों में 75 फीसद अमेरिकंस, करप्ट सिस्टम और पुलिस की सांठगांठ से लगे हुए हैं। ड्रग तस्करी में मात्र 25 प्रतिशत प्रवासी संलग्न दिखे। अर्थात्, अपने ही घर में ट्रम्प प्रशासन इसे रोक पाने में नाकारा साबित हुआ है।

भारत में अंडरवर्ल्ड के गिने-चुने सयाने, फेंटानिल को समझ पाए हैं। 2018 में इंदौर में एक अवैध फेंटानिल लैब का भंडाफोड़ हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से पता चलता है, कि 'सिनालोआ ड्रग कार्टेल' से जुड़ा एक भारतीय नागरिक शुरू में संगठन को फेंटानिल प्रीकर्सर केमिकल, एनपीपी और एएनपीपी सप्लाई करता था, जिसे कार्टेल से जुड़ा एक चीनी नागरिक फेंटानिल बनाता था और उसे भारत के बरास्ते मैक्सिको भेजता था। दिसंबर, 2018 में, मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल ने लगभग 100 किलोग्राम 'फेंटानिल प्रीकर्सर एनपीपी' जब्त किया, जिसमें चार भारतीय पकड़े गए। 6 जनवरी, 2025 को न्यूयॉर्क में गुजराती ड्रग तस्कर, भावेश लाठिया को गिरफ्तार किया गया। भावेश, 'रक्सटर केमिकल्स' का संस्थापक और 'एथोस केमिकल्स' का पूर्व निदेशक रहा है। भावेश लाठिया पर आरोप है कि उसने एक प्रीकर्सर केमिकल पर गलत लेबल लगाकर उसे एंटासिड बताया था। कोई पांच महीना पहले, 18 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर एक हेडलाइन नुमायां हुई- 'फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने के कारण भारतीय कंपनी के अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के अमेरिकी वीज़ा रद्द।' बताया गया, कि नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने के आधार पर कुछ बिजनेस और कॉर्पोरेट लीडरशिप के वीज़ा रद्द कर दिए हैं।

दरअसल, फेंटानिल से गर्भ-नाल का सम्बद्ध चीन का रहा है। शी चिनफिंग का यह देश, फेंटानिल निर्माण से लेकर दुनियाभर में सप्लाई का नेटवर्क संभाले हुए है, जिसमें ज्यादातर लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। मादुरो तो सबसे कमज़ोर मुर्गा है। कार्रवाई दरअसल, चीन पर होनी चाहिए थी। ब्यूनस आयर्स में जी-20 समिट के दौरान, चीनी राष्ट्रपति शी, फेंटानिल को एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस के रूप में लेबल करने पर सहमत हुए, जिसे व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने एक 'शानदार मानवीय कदम' बताया था। उसके अगले साल घोषणा हुई कि 1 मई, 2019 से, चीन ने आधिकारिक तौर पर फेंटानिल के सभी रूपों को दवाओं की एक श्रेणी के रूप में नियंत्रित किया। इसने उस प्रतिबद्धता को पूरा किया जो राष्ट्रपति शी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। लेकिन, यह केवल दिखाने भर की कवायद थी।

डार्कनेट मार्केट, वेब पर एक कमर्शियल वेबसाइट है, जिसके ज़रिये नशीले पदार्थ, अवैध हथियार, चोरी किया हुआ डेटा, नकली दस्तावेज़ों का लेन-देन होता है। 'सिल्क रोड', जो 2011 में लॉन्च हुआ, एक डार्कनेट मार्केट था, वह बिटकॉइन के शुरुआती यूज़र्स में से कुछ का ठिकाना था। बाद में पता चला 'सिल्क रोड', फेंटानिल के तस्करों के लिए कोड वर्ड है। ऐसे कई सारे कोडवर्ड 'चाइना गर्ल', 'चाइना व्हाइट', 'व्हाइट ड्रैगन' जैसे नामों से डार्कनेट पर नमूदार हुए। इनके पेमेंट बिटकॉइन के ज़रिये होने लगे, जिसने 'ट्रंप मेमेकॉइन' का नुकसान किया। ब्लूमबर्ग के अनुसार, 'ट्रम्प परिवार की नेट वर्थ लगभग 7.7 बिलियन डॉलर से घटकर 6.7 बिलियन डॉलर हो गई, जो डिजिटल एसेट्स में गिरावट से जुड़ी है।' कुछ रणनीतिकारों में माना है, कि फेंटानिल प्रोडक्शन से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी-आधारित लेन-देन ने 'ट्रंप मेमेकॉइन' का भट्ठा बैठाया है। ट्रम्प केवल खिसियानी बिल्ली नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सीधा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर झपट्टा मारा। लेकिन क्या, इससे फेंटानिल की तस्करी रुक जाएगी?

प्रेरणा

पत्थर के भीतर छिपा मनुष्य

एक पुरानी लेकिन अत्यंत अर्थपूर्ण कथा है। एक कला प्रेमी, जो जीवन में सौंदर्य और अर्थ की तलाश में था, महान इतालवी मूर्तिकार माइकल एंजेलो की कृति 'डेविड' के सामने देर तक खड़ा रहा। संगमरमर का वह पिंड उसे पत्थर नहीं, बल्कि जीवित चेतना जैसा प्रतीत हुआ। उसकी आँखों में सवाल था और मन में विस्मय। उसने माइकल एंजेलो से पूछा कि आखिर आपने इस निर्जीव पत्थर में इतना जीवन कैसे भर दिया। माइकल एंजेलो का उत्तर जितना सरल था, उतना ही गहरा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बनाया नहीं, बस उस हिस्से को हटा दिया जो मूर्ति नहीं था। मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के भीतर मौजूद थी।

यह उत्तर केवल कला की प्रक्रिया नहीं बताता, बल्कि जीवन की दिशा भी समझाता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसे बेहतर बनने के लिए खुद में बहुत कुछ जोड़ना होगा। उसे लगता है कि अधिक धन, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक ज्ञान या अधिक अधिकार मिलने से वह पूर्ण हो जाएगा। इसी जोड़ने की मानसिकता में वह लगातार भागता रहता है। पर यह भागदौड़ उसे भीतर से थका देती है। वह यह नहीं समझ पाता कि वास्तविक पूर्णता बाहर से कुछ जोड़ने में नहीं, बल्कि भीतर जमी अनावश्यक परतों को हटाने में है।

हर मनुष्य के भीतर एक सुंदर, शांत और संतुलित स्वरूप जन्म के साथ ही मौजूद होता है। बचपन में उसकी झलक साफ दिखाई देती है। बच्चा सरल होता है, सहज होता है और बिना किसी स्वार्थ के हँसता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, समाज की अपेक्षाएँ, असफलताओं का डर, तुलना की आदत और स्वयं को साबित करने की मजबूरी उस पर परत दर परत चढ़ती जाती है। धीरे-धीरे भीतर का सच्चा स्वरूप दबने लगता है और ऊपर से एक कठोर आवरण बन जाता है। क्रोध उस आवरण की पहली मोटी परत है। यह हमें क्षणिक संतोष तो देता है, लेकिन लंबे समय में हमारे संबंधों और मानसिक शांति को तोड़ देता है। क्रोध के क्षण में हम जो शब्द बोलते हैं, वे पत्थर की तरह भारी होते हैं और लंबे समय तक असर छोड़ते हैं। जब हम क्रोध को पहचानकर उसे हटाने का प्रयास करते हैं, तब भीतर धैर्य और समझ का स्थान बनता है। अहंकार दूसरी परत है, जो हमें स्वयं से दूर कर देती है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, इसलिए हमें बदलने या सीखने की आवश्यकता नहीं। यह परत जितनी मोटी होती जाती है, उतना ही मनुष्य भीतर से अकेला होता जाता है।

ईर्ष्या एक ऐसी परत है जो चुपचाप मन में घर कर लेती है। यह हमें दूसरों की सफलता से दुखी करती है और अपनी उपलब्धियों का आनंद भी छीन लेती है। ईर्ष्या में जीने वाला व्यक्ति हमेशा असंतोष में रहता है। जब यह परत हटती है, तब मन में संतुलन आता है और हम अपनी यात्रा को स्वीकार करना सीखते हैं। भय भी एक बड़ी परत है। असफल होने का डर, अस्वीकार होने का डर और भविष्य का डर मनुष्य को जकड़ कर रखता है। भय हमें नए कदम उठाने से रोकता है और भीतर की संभावनाओं को दबा देता है।

इन सभी परतों को हटाना आसान नहीं है। जैसे मूर्तिकार हर वार सोच-समझकर करता है, वैसे ही आत्मपरिष्कार में भी जल्दबाज़ी नहीं चलती। आत्मचिंतन, संयम और धैर्य ही वह औज़ार हैं, जिनसे भीतर की सफाई होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से देखते हैं, तब हमें समझ आने लगता है कि कौन-सी बात हमें भीतर से भारी कर रही है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या पीड़ादायक, हमें कुछ हटाने का अवसर देता है, यदि हम उससे सीख लेना जानें।

आज का समाज बाहरी चमक पर अधिक ध्यान देता है। हम चेहरे पर मुस्कान लगाना सीख लेते हैं, लेकिन भीतर की उलझनों को छुपाते रहते हैं। सोशल दिखावे की इस दुनिया में मनुष्य अपनी असली पहचान से दूर होता जा रहा है। माइकल एंजेलो का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि सत्य में है। जब हम अपने भीतर की परतों को हटाते हैं, तब हमें किसी मुखौटे की आवश्यकता नहीं रहती।

यह दृष्टि हमें दूसरों को देखने का नजरिया भी बदल देती है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही कठोर या नकारात्मक क्यों न लगे, भीतर कहीं न कहीं एक संवेदनशील और सुंदर मनुष्य को छुपाए हुए है। यदि हम केवल उसकी बाहरी परतों पर ध्यान दें, तो हम उसके सत्य तक नहीं पहुँच पाएँगे। करुणा और समझ वही दृष्टि है, जो पत्थर में छिपी मूर्ति को पहचान सकती है।

अंततः जीवन किसी नई आकृति को गढ़ने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा है। हम जो खोज रहे हैं, वह हमारे भीतर ही मौजूद है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि हम साहस के साथ उन अनावश्यक हिस्सों को हटाना शुरू करें, जो हमें बोझिल बनाते हैं। जैसे-जैसे ये परतें हटती जाती हैं, भीतर का प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। तब जीवन सरल भी लगता है और अर्थपूर्ण भी। यही वह क्षण है, जब मनुष्य समझ पाता है कि वह पत्थर नहीं था, बल्कि पत्थर के भीतर छिपी एक सुंदर, जीवंत मूर्ति था, जिसे बस प्रकट होने का अवसर चाहिए था।

कूटनीति में बौद्ध विरासत का उपयोग, भारत का अपनी बौद्ध विरासत पर नियंत्रण रखना और स्वयं को उसका पालक दिखाना आवश्यक

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष केवल कलाकृतियां नहीं हैं। ये हमारी विरासत एवं सभ्यता का अभिन्न हिस्सा हैं और भारत इसका संरक्षक है। पिपरहवा अवशेषों को एक सदी से अधिक समय बाद देश वापस लाया गया है। भारत लाए जाने के बाद इन अवशेषों को रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में ले जाया गया, जहां 1.5 लाख से अधिक भक्तों ने उनका अवलोकन किया। इसके अलावा उन्हें भूटान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड भी ले जाया गया।

भारत से निकले असंख्य ज्ञानी भिक्षुओं के कारण बौद्ध धर्म दुनिया के अनेक देशों में प्रचलित और स्वीकार्य है। चूंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में शासक आपसी संवाद में बौद्ध धर्म को बहुत महत्व देते थे, इसलिए विश्व सुलह और शांति के लिए बौद्ध धर्म का उपयोग स्वाभाविक है। वर्तमान एशिया में लगभग 45 करोड़ बौद्ध रहते हैं, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म एक साफ्ट पावर है। भारत से ही बौद्ध धर्मावलंबी तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम आदि गए। बौद्ध धर्म पर आधारित कूटनीति चलाना भारत के लिए नई बात नहीं है। मनमोहन सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इस विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य शास्त्रीय भाषा पाली का प्रचार-प्रसार करना और एशिया से छात्रों और शोधकर्ताओं को भारत आकर्षित करना भी है। बौद्ध धर्म का कूटनीतिक उपयोग मोदी सरकार का एक अंग बन गया है। इस संदर्भ में यह ठीक ही कहा गया है कि कि मोदी सरकार की नीति है-हिंदू संस्कृति, बौद्ध विरासत।

पिपरहवा अवशेषों की कहानी भी दिलचस्प है। 1898 में अमूल्य रत्न उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में अंग्रेज जमींदार विलियम पेप को मौर्यकालीन स्तूप की खोदाई में मिले। उनके साथ कुछ अस्थि-अवशेष एक कलश में पाए गए, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी में उत्कीर्ण था कि स्वयं भगवान बुद्ध के शाक्य कुल के सदस्यों ने इसे यहां रखा है। अंग्रेजों ने कुछ रत्न श्याम (प्राचीन थाईलैंड) के बौद्ध नरेश को उपहार में दिए, कुछ श्रीलंका और म्यांमार के बौद्ध मंदिरों में भेजे और एक हिस्सा कोलकाता के संग्रहालय में रखा और करीब 334 रत्नाभूषण जमींदार पेप ने अपने पास रखे। इन्हें बीते साल उनके वंशजों ने एक नीलामी घर सूथबीज को बोली लगाने के लिए सौंप दिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सूथबीज को नोटिस भेज नीलामी रुकवाई और गोदरेज समूह ने इस अमूल्य धरोहर को भारत लाने में आर्थिक योगदान दिया, पर हर देश ऐसा नहीं कर पाता।

कोरियाई युद्ध के बाद हजारों-हजार बौद्ध पुरावशेष चोर बाजार में हाथों-हाथ बिके। कोरिया में बौद्ध धर्म का सबसे तेजी से ह्रास हुआ है, पर अपने आसपास के बौद्ध देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए बड़े पैमाने पर वहां बौद्ध गोष्ठियां होती हैं। कभी चोल साम्राज्य और तदनंतर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव में रहे दक्षिण-पूर्वी एशिया देशों की हमने उपेक्षा की। इसका फायदा पहले पश्चिमी देशों और फिर चीन ने उठाया। 2000 में मीकांग-गंगा कोआपरेशन के तहत भारत ने पांच आसियान देशों कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के साथ-साथ परिवहन और संचार क्षेत्र में सहयोग की पहल की।

आज ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में कई संसाधनसंपन्न विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और पाली के पठन-पाठन के माध्यम से अपने राजनीतिक हित पूरे कर रहे हैं। इससे बौद्ध धर्म के अध्ययन में अप्रासंगिक त्रुटियां घर कर जाने का खतरा है, जो चिंताजनक है। हमें यह समझना चाहिए कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म पालन और संरक्षण में हमारी स्वाभाविक और निर्णायक भूमिका है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गांधार सभ्यता और उसकी शैव और बौद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भारत की है।

अपने बौद्ध स्थलों का हवाला देते हुए कुछ समय पहले पाकिस्तानी राजदूत नबील मुनीर ने कहा था कि बौद्ध धर्म पाकिस्तान से कोरिया गया और वहां प्रचलित महायान बौद्ध धर्म का उद्भव भी पाकिस्तान में ही हुआ। भारत अगर पाकिस्तान की ऐसी कुटिलता का प्रत्युत्तर नहीं देगा और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म नामक वृक्ष की ही एक डाली नहीं कहेगा, तो पाकिस्तान हमारी अनमोल विरासत को हथिया सकता है। बौद्ध धर्म का सर्वेसर्वा बनने के लिए चीन भी हाथ-पांव मार रहा है। दरअसल जब भारत अपना भविष्य यूरोप और अमेरिका में देख रहा था, तब बौद्ध धर्म के सहारे चीन एशिया में अपने पांव जमा रहा था।

भारत को आज ज्यादा से ज्यादा मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति में बौद्ध धर्म पर आधारित कूटनीति बहुत कारगर हो सकती है। इसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि हम वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म से प्रभावित जनता की सद्भावना आकर्षित कर सकें। भारत का अपनी बौद्ध विरासत पर नियंत्रण रखना और स्वयं को उसका पोषक दिखाना आवश्यक हो चुका है। आज विश्व दो धुरियों में विभाजित है। एक अमेरिका और दूसरा चीन के नेतृत्व में। सर्वस्वीकार्य तीसरा ध्रुव बनने के लिए हमें हिंदुत्व और बौद्ध धर्म का समान प्रतिनिधित्व करना होगा। हमें अपने विमर्श और आख्यान का नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा।

अभियान

श्री रुक्मिणी अष्टकम: विवाह, वैभव और वैकुण्ठीय करुणा का दिव्य सेतु

भारतीय सनातन परंपरा में जब भी सौभाग्य, समृद्धि और गृहस्थ जीवन की पूर्णता की बात आती है, तब मां लक्ष्मी का स्मरण स्वतः हो जाता है। वही लक्ष्मी तत्व जब प्रेम, निष्ठा और धर्म के साथ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रतिष्ठित होता है, तब उसका साकार रूप मां रुक्मिणी के रूप में प्रकट होता है। मां रुक्मिणी केवल द्वारका की महारानी नहीं हैं, वे वह चेतना हैं जो प्रेम को धर्म से जोड़ती हैं और वैभव को विनम्रता से। श्री रुक्मिणी अष्टकम इसी दिव्य चेतना का स्तवन है, जिसमें आठ श्लोकों के माध्यम से मां रुक्मिणी की कृपा, सौभाग्य और लक्ष्मी स्वरूप का आवाहन किया जाता है। यह स्तोत्र न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि विवाह, दांपत्य और धन-संपदा से जुड़े जीवन के सूक्ष्म अवरोधों को भी धीरे-धीरे दूर करने की सामर्थ्य रखता है।

मां रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि वे केवल ऐश्वर्य की देवी नहीं हैं, बल्कि धर्मसम्मत ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग यह सिखाता है कि सच्चा वैभव वही है जो धर्म, मर्यादा और प्रेम के साथ जुड़ा हो। श्रीकृष्ण से उनका विवाह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसी कारण श्री रुक्मिणी अष्टकम का पाठ करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने की मान्यता है, क्योंकि यह स्तोत्र आत्मिक स्तर पर उस ऊर्जा को सक्रिय करता है जो योग्य संबंध, सही समय और ईश्वरीय अनुकम्पा को आकर्षित करती है।

जो जातक विवाह में विलंब, अनावश्यक अड़चनें, संबंधों में अस्थिरता या बार-बार टूटते रिश्तों से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए यह स्तोत्र एक आध्यात्मिक औषधि की तरह कार्य करता है। नियमित पाठ से मन की ग्रंथियां खुलती हैं, अवचेतन में छिपे भय शांत होते हैं और व्यक्ति स्वयं को प्रेम और विश्वास के लिए तैयार करने लगता है। मां रुक्मिणी का स्मरण केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता, बल्कि भीतर की तैयारी को भी पूर्ण करता है, और जब भीतर तैयारी हो जाती है, तब बाहर की राह अपने आप खुलने लगती है।

दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए भी श्री रुक्मिणी अष्टकम का विशेष महत्व बताया गया है। आज के समय में जब संबंधों में संवाद की कमी, अहंकार और अपेक्षाओं का बोझ बढ़ता जा रहा है, तब मां रुक्मिणी की करुणा एक संतुलन का कार्य करती है। वे प्रेम को समर्पण से जोड़ती हैं और अधिकार को कर्तव्य से। इस स्तोत्र के पाठ से पति-पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है, छोटी-छोटी बातों पर होने वाले तनाव कम होते हैं और एक-दूसरे के प्रति स्वीकार्यता बढ़ती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का स्वाभाविक परिवर्तन है, जो नियमित साधना से घटित होता है।

मां रुक्मिणी को लक्ष्मी स्वरूप मानने के कारण इस स्तोत्र का सीधा संबंध धन, वैभव और सुख-संपदा से भी जोड़ा गया है। लेकिन यहां यह समझना आवश्यक है कि यह धन केवल भौतिक नहीं होता। यह स्थिर आय, आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण और जीवन में संतोष की भावना के रूप में भी प्रकट होता है। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो केवल धन नहीं देतीं, बल्कि उसे संभालने की बुद्धि भी प्रदान करती हैं। श्री रुक्मिणी अष्टकम का नियमित पाठ व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता और संतुलन की भावना जगाता है, जो लक्ष्मी तत्व को स्थिर करता है। पाठ विधि की बात करें तो यह स्तोत्र सरल है, लेकिन श्रद्धा और नियमितता इसकी आत्मा है। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में या संध्या समय शांत वातावरण में स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो मां रुक्मिणी और श्रीकृष्ण का चित्र या विग्रह सामने रखें।

दीप प्रज्वलित करें, मन को कुछ क्षण स्थिर करें और फिर श्रद्धा भाव से अष्टकम का पाठ करें। उच्चारण की शुद्धता जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भाव की शुद्धता है। यदि संस्कृत उच्चारण में कठिनाई हो, तो भावार्थ को समझते हुए मन ही मन भी पाठ किया जा सकता है।

पाठ की संख्या को लेकर परंपरा में विभिन्न मान्यताएं मिलती हैं। सामान्यतः एक बार का नित्य पाठ भी फलदायी माना गया है, लेकिन यदि विवाह संबंधी विशेष बाधा हो या दांपत्य जीवन में गहरा तनाव हो, तो 11, 21 या 40 दिनों तक नियमित पाठ करने की सलाह दी जाती है। कुछ साधक शुक्रवार के दिन विशेष रूप से इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, क्योंकि शुक्रवार मां लक्ष्मी का प्रिय दिन माना जाता है। उस दिन सफेद या हल्के रंग के वस्त्र, सुगंधित पुष्प और सात्त्विक आहार के साथ पाठ करने से साधना और भी प्रभावी मानी जाती है।

इस स्तोत्र का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। घर का वातावरण भी धीरे-धीरे सकारात्मक होने लगता है। जहां पहले अनावश्यक विवाद, बेचैनी या आर्थिक चिंता रहती थी, वहां शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मां रुक्मिणी की कृपा केवल व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवेश पर पड़ती है। वे गृहस्थ जीवन की अधिष्ठात्री हैं और उनका आशीर्वाद घर को वास्तव में गृह बना देता है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो श्री रुक्मिणी अष्टकम आत्मा को श्रीकृष्ण के समीप ले जाने वाला स्तोत्र है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम मांग नहीं करता, समर्पण करता है। मां रुक्मिणी का जीवन त्याग, साहस और अडिग विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने धर्म के लिए, प्रेम के लिए और सत्य के लिए सभी भौतिक भय त्याग दिए। जब साधक इस भाव से उनका स्मरण करता है, तब उसके भीतर भी साहस और स्पष्टता का जन्म होता है। वह जीवन के निर्णयों में अधिक दृढ़ और संतुलित बनता है।

आज के युग में जब लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि आध्यात्मिक साधना कोई सौदा नहीं है। श्री रुक्मिणी अष्टकम का पाठ भी तभी पूर्ण फल देता है, जब वह श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ किया जाए। मां रुक्मिणी की कृपा चुपचाप कार्य करती है। वह जीवन की दिशा को धीरे-धीरे सुधारती है, सही लोगों को जीवन में लाती है और गलत परिस्थितियों को स्वतः दूर कर देती है।

अंततः श्री रुक्मिणी अष्टकम केवल विवाह या धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि जीवन को सौम्यता, संतुलन और प्रेम से भरने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह स्तोत्र हमें याद दिलाता है कि लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं, जहां धर्म, प्रेम और विनम्रता साथ-साथ चलते हैं। जो साधक इस सत्य को समझकर मां रुक्मिणी का स्मरण करता है, उसके जीवन में दिव्य आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगता है, और वही प्रवाह उसे सुख, समृद्धि और शांति की ओर ले जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

महाप्रबंधक पश्चिम एवं मध्य रेलवे ने साबरमती महेसाणा–पालनपुर सेक्शन का किया विस्तृत निरीक्षण

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे द्वारा रेल संरक्षा एवं आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर अग्रसर विभिन्न विकासात्मक एवं संरक्षा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। दिनांक 07.01.2026 को महाप्रबंधक पश्चिम एवं मध्य रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ साबरमती–कलोल–महेसाणा–पालनपुर रेल खंड का विस्तृत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान साबरमती से पालनपुर के बीच रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, छोटे एवं प्रमुख पुलों, पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग, सेक्शन कर्व्स तथा विभिन्न संरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की गई। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों के साथ संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। कलोल, महेसाणा एवं पालनपुर स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। साथ ही मास्टर केबिन, बुकिंग काउंटर, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम सहित विभिन्न आधारभूत संरचना कार्यों का निरीक्षण किया गया।

साबरमती–कलोल खंड के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 240 (SPL) का गहन निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त कलोल रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रगति पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का भी जायजा लिया गया। डांगरवा स्टेशन यार्ड में पॉइंट्स संख्या 107 (किमी 743/294) तथा कर्व संख्या 116 की संरक्षा जांच की गई। साथ ही प्रमुख पुल संख्या 965 DN (कॉम्पोज़िट गर्डर) का निरीक्षण किया गया। खारी नदी पर स्थित मेजर ब्रिज संख्या 965 (किमी 719/28-8) तथा पी-वे गैंग संख्या 13 एवं 14 का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महाप्रबंधक ने गैंगमैनों से संवाद कर कार्य के दौरान उपयोग किए जा रहे सेफ्टी उपकरणों- जैसे सेफ्टी शूज, जैकेट एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता एवं समय पर आपूर्ति की जानकारी ली।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत महेसाणा स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही आरपीएफ पोस्ट, आरआरआई रूम, टीआरडी डिपो, एसएसपी कार्यालय, रेलवे हेल्थ यूनिट तथा रेलवे कॉलोनी की सुविधाओं का अवलोकन कर यात्री एवं कर्मचारियों से जुड़ी सुविधाओं का आकलन किया गया। उंझा–कामली के बीच RUB नं. 932A एवं ब्रिज संख्या 927D के स्पान का भी निरीक्षण किया गया।

मीडिया से संवाद करते हुए महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस प्रकार के निरीक्षणों के माध्यम से रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, पुलों, पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग तथा कर्व्स का विभिन्न संरक्षा मानकों के अनुरूप वार्षिक परीक्षण किया जाता है, जिससे सुरक्षित एवं सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने बताया कि आंबलियासन–विजापुर तथा आदरज मोटी–विजापुर के बीच गेज परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस सेक्शन का CRS निरीक्षण भी संपन्न हो गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इस मार्ग पर नई रेल सेवाओं का परिचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।

महेसाणा–पालनपुर सेक्शन में रेलवे लाइन के डबलिंग कार्य के पूर्ण होने से ट्रेन परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे के कुल 1337 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें पश्चिम रेलवे के 108 स्टेशन शामिल हैं।

अहमदाबाद एवं साबरमती स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 9 से 12 तथा साबरमती स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर कार्य प्रगति पर है, जो मार्च–अप्रैल 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके पश्चात दोनों स्टेशनों पर अधिक ट्रेनों का ठहराव संभव होगा, जिससे नई ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।

यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों के लिए रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से लगभग दोगुना करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम रेलवे से लगभग 256 ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो आगामी पाँच वर्षों में बढ़कर लगभग 450 हो जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, रेलवे फाटक मुक्त अभियान के अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर उनके स्थान पर आरयूबी/आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। बेचराजी–रणुज रेलवे लाइन पर शीघ्र ही CRS निरीक्षण किया जाएगा, जिसके उपरांत इस सेक्शन पर भी रेल परिचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।

महाप्रबंधक ने सिद्धपुर में नवनिर्मित गुड्स शेड प्रशासनिक कार्यालय उद्घाटन किया। सिद्धपुर में नवनिर्मित जी+1 गुड्स शेड क्षेत्र में माल परिवहन संभाल क्षमता को सुदृढ़ करने तथा परिचालन दक्षता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक गुड्स शेड परिचालन आवश्यकताओं एवं हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस सुविधा में सीजीएस कक्ष, एफओआईएस कक्ष, व्यापारियों के लिए कक्ष तथा कैंटीन शामिल हैं, जिससे माल परिचालन का सुचारु समन्वय सुनिश्चित होगा और उपयोगकर्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, सुविधा और स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने हेतु पर्याप्त शौचालय सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं।

साथ ही सिद्धपुर में नवनिर्मित रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स का रेल कर्मचारी की बालिका से उदघाटन करवाया गया गया। रेलकर्मी श्री पींटू भारती, श्री मुन्नाराम और श्री रामभरण को क्वार्टर्स की चाबियाँ सौंपी गईं।

सिद्धपुर–पालनपुर सेक्शन में 130 किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल भी किया गया। पालनपुर स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त पालनपुर स्टेशन पर SPART तथा न्यू पालनपुर में रनिंग रूम का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साबरमती स्टेशन पर पुनर्विकसित कार्यों का अवलोकन किया गया तथा लोकोमोटिव शेड साबरमती टीम द्वारा निर्मित वैक्यूम असिस्टेड ट्रैक क्लीनर (VAT क्लीनर) मशीन का परीक्षण भी किया गया।

अपने निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री गुप्ता ने रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों, एसोसिएशनों, जन प्रतिनिधियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा गणमान्य नागरिकों से भी भेंट कर संवाद किया।

इस अवसर पर मुख्यालय से आए विभिन्न विभागों के प्रधान विभागाध्यक्षों सहित मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

भावनगर रेलवे मंडल की वर्ष 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ,संरक्षा, यात्री सुविधाओं, आधुनिकरण एवं राजस्व वृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने वर्ष 2025 के दौरान रेल संरक्षा, यात्री सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण तथा राजस्व अर्जन के क्षेत्र में अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से मंडल ने सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आधुनिक रेल सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

संरक्षा एवं आधारभूत ढांचे में सशक्त सुधार

भावनगर मंडल में रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2025 के दौरान 17 लेवल क्रॉसिंग का उन्मूलन आरओबी/आरयूबी निर्माण, डायवर्जन एवं प्रत्यक्ष बंदीकरण के माध्यम से किया गया। इस अवधि में 5 आरयूबी एवं 1 आरओबी का निर्माण पूर्ण हुआ। यात्रियों की सुविधा हेतु सिहोर जंक्शन पर नया फुट ओवर ब्रिज लोकार्पित किया गया तथा मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 12 नए एफओबी प्रस्तावित/निर्माणाधीन हैं।

अतिक्रमण रोकने हेतु 9.245 किलोमीटर बाउंड्री वॉल का निर्माण तथा जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दामनगर–लीलिया मोटा खंड में अतिरिक्त वाटर-वे ब्रिज का निर्माण भी पूर्ण किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत महुवा, राजुला जं., जामजोधपुर, सिहोर जं., लींबडी एवं पालिताना स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया।

सुरक्षा, आधुनिकीकरण एवं बेहतर यात्रा अनुभव

रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर (HABD) प्रणाली लिलिया मोटा, राणपुर, तरसई एवं चोकी स्टेशनों पर स्थापित की गई। खोडियार मंदिर स्टेशन पर 29.10.2025 को इलेक्ट्रॉनिक इन-मोशन वेइंग सिस्टम चालू किया गया, जिससे ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ।

यात्रियों की सुरक्षा एवं आराम को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख ट्रेनों के रेक ICF से आधुनिक LHB कोचों में परिवर्तित किए गए। इसके अतिरिक्त भावनगर–अयोध्या कैंट के बीच नई साप्ताहिक LHB ट्रेन

सेवा 03.08.2025 से प्रारंभ की गई। वेरावल-साबरमती के बीच 26.05.2025 से "वंदे भारत एक्सप्रेस" (सप्ताह में 6 दिन, गुरूवार को छोड़कर) शुरू की गई है। इसके अलावा पोरबंदर-राजकोट के बीच 14.11.2025 से 02 नई यात्री ट्रेन भी शुरू की गई है। भविष्य की योजनाओं में 136 करोड़ की लागत से राणावाव में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो तथा 98 करोड़ की लागत से अदितपरा (पोरबंदर) में आधुनिक बूट लॉन्ड्री का प्रस्ताव शामिल है।

यात्रियों की सुरक्षा एवं मानवीय सेवा

RPF भावनगर मंडल द्वारा वर्ष 2025 में यात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए गए। ऑपरेशन अमानत के तहत 39.80 लाख से अधिक मूल्य की खोई हुई संपत्ति यात्रियों को सुरक्षित लौटाई गई। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत 35 बच्चों को रेस्क्यू कर परिजनों से मिलाया गया। रेल संपत्ति चोरी, अवैध यात्रा, अतिक्रमण, स्टोन पेल्टिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम हेतु निरंतर कार्रवाई एवं जन-जागरूकता अभियान चलाए गए। एक उल्लेखनीय मानवीय उदाहरण में, RPF कर्मी द्वारा दिनांक 30.04.2025 को गोंडल स्टेशन पर समय पर CPR देकर एक यात्री की जान बचाई गई, जिसकी व्यापक सराहना हुई।

यात्री सुविधाएँ एवं राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि

भावनगर मंडल ने यात्री सुविधाओं पर 170 करोड़ से अधिक का निवेश कर डिजिटल उद्घोषणा प्रणाली, गाइडेंस बोर्ड, एफओबी, प्लेटफॉर्म उन्नयन एवं स्टेशन पुनर्विकास कार्य पूर्ण किए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी से दिसंबर 2025 तक) में:

- कुल राजस्व 1375.94 करोड़ (जनवरी से दिसंबर 2025 तक) प्राप्त हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 अप्रैल से दिसंबर-2025 तक 1061.36 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।
- 29.50 करोड़ का सर्वाधिक मासिक (नवंबर-2025) एवं 1.31 करोड़ का सर्वाधिक दैनिक (29.10.2025) यात्री राजस्व दर्ज किया गया है तथा माल ढुलाई में भी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की गईं हैं।
- एक माह में सर्वाधिक उर्वरक के 94 रेक लोड कर 46.83 करोड़ (दिसंबर-2025 में) प्राप्त हुआ है।
- एक माह में सर्वाधिक एलपीजी के 77 रेक लोड कर 21.92 करोड़ का राजस्व अप्रैल-2025 में प्राप्त हुआ है।
- टिकट जांच से एक दिन में 9.05 लाख (15.10.2025) का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुआ
- एक ही EFT में टिकट जांच स्टाफ द्वारा अब तक की सर्वाधिक वसूली — 78,060/-, श्री राजन कुमार सिंह, सीटीआई/वेरावल द्वारा दिनांक 22.12.2025 को की गई।
- NFR में 14.5% एवं संड्री रेवेन्यू में 16.6% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- पहली बार गेम जोन जूनागढ़ में 19.11.2025 से शुरू किया गया है।

भावनगर मंडल की अन्य उपलब्धियां

- भावनगर परा रेलवे स्टेशन पर यात्री लिफ्ट का कमीशनिंग।
- नये मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में 135.3KWp, कम्युनिटी हॉल, भावनगर परा में 50.6 KWp कुल क्षमता 185.9 KWp का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।
- लॉन्ग-हॉल कंटेनर ट्रेनों का रिकॉर्ड: एक माह में सर्वाधिक PPSP से 43 ट्रेनों का परिचालन।
- 68वीं पेंशन अदालत (दिसंबर-2025) में 225 मामलों का निस्तारण।
- कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर हेल्प डेस्क कियोस्क स्थापित किए गये हैं।
- LC-35 (सरखेज–मोरैया) का इंटरलॉकिंग कार्य 30.12.2025 को सफलतापूर्वक कमीशंड।
- धोला-सुरेन्द्रनगर सेक्शन में बोटाद स्टेशन पर ट्रैक मेंटेनेंस डिपो का 11.11.2025 को कमीशनिंग किया गया।
- मंडलीय रेल चिकित्सालय (DRH) भावनगर में नवजात शिशुओं के लिए फोटोथेरेपी यूनिट का कमीशनिंग; पीलिया (हाइपरबिलिरुबिनेमिया) के उपचार में प्रभावी लाभ।
- वर्ष 2025 के दौरान 04 (भावनगर परा, राणपुर, वीरपुर एवं सिहोर जं.) FOB तैयार हो चुके हैं, 12 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है और 7 स्टेशनों के लिए कार्य प्रस्तावित है।
- मंडल के 16 स्टेशनों पर 40 लिफ्ट का कार्य प्रगति पर है तथा 6 लिफ्ट प्रस्तावित है।
- वर्ष 2025 के दौरान 12 स्टेशनों पर कोच इंडिकेटर लगाए जा चुके हैं, 21 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।
- मंडल के 12 स्टेशनों पर प्रतिक्षालय (Waiting Room) बनाए जा चुके हैं, 3 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है।
- प्लेटफार्म को हाई लेवल करना अथवा विस्तारित करने का कार्य 17 स्टेशनों पर पूर्ण हो चुका है, 03 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है तथा 47 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
- पेंशनरों को पेंशन से सम्बंधित होने वाली समस्याओं का सही समय पर उचित समाधान किया जाता है।
- वित्त अनुभाग, लेखा विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 की अवधि के दौरान कुल 4085 मामलों/प्रस्तावों की गहन जाँच की गई। उक्त अवधि में किए गए प्रस्तावों के माध्यम से कुल 98.80 करोड़ की बचत हुई।
- भावनगर मंडल द्वारा वर्ष 2025 में किए गए समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप रेल संरक्षा, यात्री सुविधा, सेवा गुणवत्ता, समयपालन एवं राजस्व अर्जन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित हुए हैं। पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल भविष्य में भी यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक, सुविधाजनक एवं विश्वसनीय रेल सेवाएँ प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के 41 कार्यों के लिए केन्द्रीय सड़क एवं अवसरंचना निधि से 1078 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए

- **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा गांधीनगर में नवंबर-2025 में आयोजित बैठक की फलश्रुति**
- **कुल 564.57 किलोमीटर लंबाई में वाइडनिंग, स्ट्रेंदनिंग, रिसरफेसिंग तथा स्ट्रक्चर के विभिन्न कार्य शुरू किए जाएंगे**
- **कनेक्टिविटी तथा ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अधिक गति मिलेगी, पीएम गति शक्ति अंतर्गत लॉजिस्टिक्स परिवहन में सरलता होगी**

(जीएनएस)। गांधीनगर : गांधीनगर, 07 जनवरी : भारत सरकार की केन्द्रीय सड़क एवं अवरसंरचना निधि (सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड- सीआरआईएफ) से गुजरात को राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1078.13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

गुजरात में राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के कार्यों के लिए आवंटित की गई इस बड़ी राशि से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को सुदृढ़ बनाकर कनेक्टिविटी तथा ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को गति देने का दृष्टिकोण साकार होगा। इतना ही नहीं; पीएम गति शक्ति अंतर्गत लॉजिस्टिक्स परिवहन में सरलता होगी और वह तेज बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा राज्य के सड़क मार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए गत नवंबर-2025 में गांधीनगर में आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक की फलश्रुति के रूप में गुजरात को 1078.13 करोड़ रुपए की यह राशि राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के कार्य शुरू करने के लिए आवंटित की गई है।

सीआईआरएफ की जो यह राशि राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क मार्गों के कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है, उससे कुल 564.57 किलोमीटर लंबाई में विभिन्न 41 कार्य शुरू किए जाने वाले हैं।

तद्अनुसार; पाटण, कच्छ, बनासकाँठा, खेडा, महीसागर, छोटा उदेपुर, वलसाड, अमरेली, जामनगर तथा वडोदरा जिलों में राज्य राजमार्गों पर 229.20 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण के 11 कार्य शुरू करने के लिए 636 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।

सड़क सुदृढ़ीकरण तथा पुनः सतहीकरण के जो 23 कार्य 335.37 किलोमीटर में 408.33 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले हैं; उनमें अहमदाबाद, खेडा, आणंद, अरवल्ली, महीसागर, तापी, नवसारी, देवभूमि द्वारका, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, सूरत तथा जामनगर जिलों के कार्यों का समावेश होता है।

इन कार्यों के अतिरिक्त; केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से स्ट्रक्चर के (ढाँचों से जुड़े) जिन 7 कार्यों के लिए 33.80 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं; उनमें तापी, सूरत तथा डांग जिलों के कार्य शामिल किए जाएंगे।

तिलकवाड़ा स्टेशन का अपग्रेडेशन, यात्रियों के लिए नई सौगात,सेक्शन कैपेसिटी में होगी वृद्धि, अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन संभव

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के डभोई और एकतानगर स्टेशनों के बीच स्थित तिलकवाड़ा स्टेशन को D-क्लास (नॉन-ब्लॉक) स्टेशन से B-क्लास (ब्लॉक) स्टेशन में अपग्रेड करने का कार्य प्रगति पर है। अब यह स्टेशन साधारण स्टॉपिंग पॉइंट से उन्नत सिग्नलिंग, एक बेहतर ऑपरेशनल क्षमता और अधिक यात्री सुविधाओं वाला स्टेशन बन जायेगा, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी।

वडोदरा मंडल में स्थित एकतानगर भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टेचू ऑफ़ यूनिटी के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में वडोदरा और एकतानगर के बीच ट्रेन का परिचालन किया जाता है। तिलकवाड़ा को B-क्लास स्टेशन में बदलने से एकतानगर और चांदोद के बीच मौजूदा सिंगल ब्लॉक सेक्शन दो ब्लॉक सेक्शन में बंट जाएगा, यानी एकतानगर – तिलकवाड़ा और तिलकवाड़ा –चांदोद। एक साधारण हॉल्ट से एक फंक्शनल ब्लॉक स्टेशन में बदलने से चांदोद और एकतानगर के बीच ट्रेन परिचालन क्षमता बढ़ेगी, जिससे संरक्षा में वृद्धि होगी। साथ ही सेक्शन कैपेसिटी बढ़ने से इस सेक्शन में और अधिक ट्रेनों को परिचालित करने का विकल्प मिलेगा। भविष्य में, ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर, तिलकवाड़ा एक फायदेमंद ऑपरेशनल पॉइंट के तौर पर काम करेगा, जिससे ट्रेन रेगुलेशन और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी। एकतानगर से शुरू होने वाली ट्रेनों का लाईन क्लियर के लिए रुकने का समय कम हो जाएगा, जिससे ऑपरेशन आसान होगा और समय की पाबंदी बेहतर होगी।

तिलकवाड़ा स्टेशन पर एक लूप लाइन का भी निर्माण किया गया है, जिससे लाइन क्षमता बढ़ेगी। ट्रेन को लूप लाइन या साइडिंग में लेकर एक अतिरिक्त ट्रेन को क्रॉसओवर देकर परिचालित कर सकेंगे। B-क्लास (ब्लॉक स्टेशन) बनने पर तिलकवाड़ा में होम/स्टार्टर सिग्नल, पॉइंट्स और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना होगी। पॉइंट्स और सिग्नल के सुरक्षित संचालन के लिए तिलकवाड़ा स्टेशन पर इंटरलॉकिंग सिस्टम की स्थापना की जा रही है। ऑपरेशन मैनेज करने के लिए रेलवे स्टाफ की तैनाती होगी।

B-क्लास स्टेशन बनने से तिलकवाड़ा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में भी इज़ाफा होगा, यात्रिओं को स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल, वेटिंग रूम और टिकट काउंटर जैसी सुविधाएँ मिलेंगी, जिससे यात्रिओं का सफ़र और सुखकर होगा। स्टेशन पर एक हाई-लेवल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान ज़्यादा सुविधा और सुरक्षा मिलेगी।

अपग्रेड होने से पहले डभोई और एकतानगर के बीच तिलकवाड़ा एक D-क्लास (फ्लैग स्टेशन) स्टेशन था, जहाँ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म और कुछ बुनियादी सुविधाएं थी। फ्लैग स्टेशन होने के कारण कोई सिग्नल नहीं था और ऑपरेशन के लिए कोई समर्पित रेलवे स्टाफ नहीं था।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है, जो 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपरोक्त कार्य के संबंध में 09/10 जनवरी, 2026 की रात को कांदिवली स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर पॉइंट्स के इंसर्शन एवं डिस्मैंटलिंग के लिए 23:15 बजे से 03:15 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 10/11 जनवरी, 2026 की रात को कांदिवली और मालाड स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर पॉइंट 101 के इंसर्शन के लिए मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर 01:00 बजे से 06:30 बजे तक तथा अप स्लो लाइन पर 01:00 बजे से 04:00 बजे तक रहेगा।

उपर्युक्त ब्लॉकों, पांचवीं लाइन के निलंबन तथा गति प्रतिबंध लगाए जाने के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित होंगी।

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:

10 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

10 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

11 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली–अहमदाबाद एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

11 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली–नंदुरबार एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

री-शेड्यूल होने वाली ट्रेनें:

1. 10 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12902 अहमदाबाद–दादर एक्सप्रेस अपने मार्ग में 20 मिनट री-शेड्यूल होगी।
2. 10 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19218 वेरावल–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 45 मिनट री-शेड्यूल होगी, अर्थात यह ट्रेन वेरावल से 12:35 बजे प्रस्थान करेगी।
3. 11 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद 30 मिनट री-शेड्यूल होगी, अर्थात यह ट्रेन 06:10 बजे प्रस्थान करेगी।
4. 11 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22921 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस, 1 घंटा री-शेड्यूल होगी, अर्थात यह ट्रेन 06:10 बजे प्रस्थान करेगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित होने वाली उपनगरीय ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक–I एवं II में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

शेयर बाजार में मजबूत एंट्री, मॉडर्न डाइग्नॉस्टिक की लिस्टिंग से निवेशकों को पहले दिन ही मुनाफा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली मॉडर्न डाइग्नॉस्टिक एंड रिसर्च सेंटर ने शेयर बाजार में उतरते ही निवेशकों को उत्साहित कर दिया। बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग सकारात्मक रही और आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को पहले ही दिन लाभ मिला। निर्गम मूल्य 90 रुपये प्रति शेयर के मुकाबले शेयरों की शुरुआत 99.50 रुपये पर हुई, जो करीब साढ़े दस प्रतिशत के प्रीमियम को दर्शाता है। यह लिस्टिंग संकेत देती है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी के बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं को लेकर मजबूत रहा। हालांकि, लिस्टिंग के बाद दिन के दौरान मुनाफावसूली का दबाव भी देखने को मिला। शुरुआती बढ़त के बाद शेयरों में कुछ नरमी आई और कारोबारी सत्र के अंत में यह 94.53 रुपये पर बंद हुए। इसके बावजूद, पहले दिन के बंद भाव पर भी निवेशकों को लगभग पांच प्रतिशत का शुद्ध रिटर्न मिला, जिसे एसएमई सेगमेंट की लिस्टिंग के लिहाज से संतोषजनक माना जा रहा है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, शुरुआती उतार-चढ़ाव के बावजूद जिस तरह से शेयर निर्गम मूल्य से ऊपर टिके रहे, वह कंपनी के प्रति सकारात्मक धारणा को दर्शाता है।

36.89 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक खुले इस निर्गम को कुल मिलाकर लगभग 377 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जो एसएमई सेगमेंट में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो संस्थागत निवेशकों के हिस्से में करीब 193 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 700 गुना से अधिक और खुदरा निवेशकों के कोटे में 340 गुना से ज्यादा आवेदन आए। यह भारी मांग इस बात का संकेत है कि निवेशकों को कंपनी के कारोबार, उसकी वित्तीय स्थिति और ग्रोथ की संभावनाओं पर भरोसा है।

आईपीओ के जरिए कंपनी ने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 40.99 लाख नए शेयर जारी किए हैं। इस निर्गम से जुटाई गई राशि का उपयोग मॉडर्न डाइग्नॉस्टिक अपनी विस्तार योजनाओं के लिए करने जा रही है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फंड का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक और उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद में लगाया जाएगा, जिससे उसकी डायग्नॉस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार होगा। इसके अलावा, मौजूदा कर्ज के आंशिक भुगतान, कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो बीते कुछ वर्षों में इसमें लगातार सुधार देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी घाटे में थी, लेकिन 2023-24 में उसने मुनाफे में वापसी की। इसके बाद 2024-25 में लाभ में और मजबूती आई, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भी कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है, जो इसके कारोबार की स्थिरता और संचालन क्षमता को दर्शाता है। इसके साथ ही, कंपनी के राजस्व में लगातार दो अंकों की वार्षिक वृद्धि बनी हुई है, जो हेल्थकेयर और डायग्नॉस्टिक सेक्टर में इसकी मजबूत पकड़ को दिखाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, नियमित जांच की मांग और आधुनिक डायग्नॉस्टिक सेवाओं की जरूरत आने वाले वर्षों में इस सेक्टर को और विस्तार देगी।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक दबाव की कूटनीति, पाकिस्तान की घबराहट और अमेरिका में तेज हुई लॉबिंग

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को किस हद तक असहज और भयभीत कर दिया था, इसका खुलासा अब अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत सार्वजनिक हुए दस्तावेजों से हुआ है। इन दस्तावेजों के अनुसार, पिछले साल अप्रैल में चार दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए अमेरिका में जबरदस्त कूटनीतिक और लॉबिंग गतिविधियां शुरू कर दी थीं। पाकिस्तान ने अपने राजनयिकों और लॉबिंग फर्मों के माध्यम से अमेरिका के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, सांसदों, पेंटागन और विदेश विभाग के अफसरों से करीब 60 बार संपर्क किया था, ताकि किसी भी तरह भारत पर दबाव बनाकर सैन्य कार्रवाई को रुकवाया जा सके।

FARA के तहत अमेरिकी न्याय विभाग में दाखिल दस्तावेज बताते हैं कि पाकिस्तानी राजनयिकों ने ईमेल, फोन कॉल और आमने-सामने बैठकों के जरिए अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के समाप्त होने के बाद तक लगातार संघर्षविराम की कोशिशें जारी रखीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को आशंका थी कि अगर हालात और बिगड़े तो उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी डर के चलते उसने अमेरिका में अपने प्रभाव का अधिकतम इस्तेमाल करने की कोशिश की और भारत के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बनवाने के लिए हर संभव रास्ता अपनाया। दस्तावेजों में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन तक तेजी से पहुंच बनाने और व्यापार तथा कूटनीतिक फैसलों को प्रभावित करने के उद्देश्य से छह अलग-अलग लॉबिंग फर्मों की सेवाएं ली थीं, जिन पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इन फर्मों का काम केवल बैठकें तय करना ही नहीं था, बल्कि अमेरिकी नीति-निर्माताओं के सामने पाकिस्तान का पक्ष रखना और भारत-पाकिस्तान तनाव को पाकिस्तान के अनुकूल ढंग से प्रस्तुत करना भी था। एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म सिडेन लॉ एलएलपी की रिपोर्ट में यह जिक्र है कि उसने भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान पाकिस्तान को अमेरिकी समर्थन दिलाने और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के प्रयासों में मदद की।

इस पूरे घटनाक्रम में भारत की ओर से भी अमेरिका के साथ सक्रिय कूटनीतिक संपर्क बनाए रखे गए थे। अमेरिकी लॉबिंग फर्म एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय दूतावास ने भी अमेरिकी सरकार और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद को प्रभावी बनाने के लिए इस फर्म की सेवाएं ली थीं। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच यह फर्म भारतीय दूतावास के लिए काम कर रही थी। FARA में दर्ज जानकारी के मुताबिक 10 मई को इस फर्म ने भारतीय दूतावास की ओर से व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स, अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिकी गिल से संपर्क कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन तक चला सैन्य टकराव समाप्त हुआ था। इन बैठकों और संपर्कों के दौरान भारत-अमेरिका व्यापार समझौते, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी मीडिया कवरेज और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। फर्म की भूमिका बैठकों की व्यवस्था करने, फोन कॉल और ईमेल के जरिए दोनों पक्षों के अधिकारियों को जोड़ने तक सीमित थी। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक कराने में भी मदद मांगी थी। FARA दस्तावेजों में कई प्रविष्टियां भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की प्रगति और रणनीति से जुड़ी बातचीत की ओर भी इशारा करती हैं।

इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका में संपर्क बढ़ाने के लिए दूतावासों, निजी कंपनियों और व्यावसायिक संगठनों द्वारा लॉबिंग फर्मों और कंसल्टेंट्स की सेवाएं लेना एक सामान्य, कानूनी और स्थापित प्रक्रिया है। भारतीय दूतावास भी 1950 के दशक से ही आवश्यकता के अनुसार ऐसी फर्मों के साथ अनुबंध करता रहा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अमेरिकी न्याय विभाग में दर्ज सभी गतिविधियां सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और इन्हें किसी भी तरह की मध्यस्थता या गुप्त सौदेबाजी के रूप में देखना गलत होगा। ुल मिलाकर, FARA दस्तावेजों से यह तस्वीर साफ होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय दबाव बनवाने के लिए अमेरिका में बेतहाशा लॉबिंग कर रहा था, वहीं भारत अपनी कूटनीतिक स्थिति को स्पष्ट और मजबूत रखने के लिए आधिकारिक और पारदर्शी तरीकों से अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में था। यह पूरा घटनाक्रम न केवल दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आधुनिक संघर्षों में सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ वैश्विक कूटनीति और लॉबिंग किस तरह अहम भूमिका निभाने लगी है।

अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय कदम रखने का लक्ष्य

(जीएनएस)। अहमदाबाद। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक लक्ष्य तय कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख एएस किरण कुमार ने कहा है कि भारत की योजना वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की है। यह बयान उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पांचवें सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर दिया, जहां वे वर्तमान में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। अपने संबोधन में एएस किरण कुमार ने कहा कि आने वाले डेढ़ दशक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद निर्णायक होंगे। उन्होंने बताया कि अब से लेकर 2040 तक इसरो और उससे जुड़ी संस्थाएं लगातार कई बड़े और जटिल अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देंगी। इन मिशनों का उद्देश्य केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति और अंतरिक्ष में दीर्घकालिक अनुसंधान की नींव रखना भी होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का लक्ष्य 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है।

एएस किरण कुमार ने यह भी बताया कि भारत केवल चंद्र मिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। यह अंतरिक्ष स्टेशन भविष्य में वैज्ञानिक प्रयोगों, मानव अंतरिक्ष उड़ानों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक अहम केंद्र बन सकता है। उनका कहना था कि अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करेगा, जिनके पास अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति बनाए रखने की क्षमता है। अपने भाषण में इसरो के पूर्व प्रमुख ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सोच और दर्शन पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश है, जिसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास मुख्य रूप से सामाजिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया है, न कि सैन्य प्रभुत्व या हथियारों की होड़ के लिए। उपग्रह संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि, शिक्षा और दूरदराज के इलाकों तक सेवाएं पहुंचाने में भारत की अंतरिक्ष तकनीक की भूमिका को उन्होंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया। किरण कुमार ने यह भी रेखांकित किया कि चंद्रयान जैसे अभियानों ने न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दुनिया के सामने रखा है, बल्कि देश के युवाओं में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति उत्साह भी जगाया है।

सोना वायदा में 867 रुपये, चांदी वायदा में 4344 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 85 रुपये की गिरावट

कमोडिटी वायदाओं में 41377.01 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 115744.23 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 32940.37 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36260 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 157127.24 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 41377.01 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 115744.23 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 36260 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2510.04 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 32940.37 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 139140 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 139140 रुपये और नीचे में 137879 रुपये पर पहुंचकर, 139083 रुपये के पिछले बंद के सामने 867 रुपये या 0.62 फीसदी गिरकर 138216 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 322 रुपये या 0.28 फीसदी गिरकर 113156 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 66 रुपये या 0.47 फीसदी गिरकर 14117 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 138947 रुपये के भाव पर खूलकर, 138991 रुपये के दिन के उच्च और 137779 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 856 रुपये या 0.62 फीसदी गिरकर 138149 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 139498 रुपये के भाव पर खूलकर, 139950 रुपये के दिन के उच्च और 138550 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 139595 रुपये के पिछले बंद के सामने 665 रुपये या 0.48 फीसदी गिरकर 138930 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 257599 रुपये के भाव पर खूलकर, 259692 रुपये के दिन के उच्च और 251729 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 258811 रुपये के पिछले बंद के सामने 4344 रुपये या 1.68 फीसदी लुढ़ककर 254467 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 3912 रुपये या 1.5 फीसदी गिरकर 256625 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3881 रुपये या 1.49 फीसदी घटकर 256645 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 5264.51 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 13.55 रुपये या 1.01 फीसदी गिरकर 1324.75 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 2.8 रुपये या 0.89 फीसदी गिरकर 312.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.56 फीसदी औंधकर 313.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 1.85 रुपये या 0.96 फीसदी की तेजी के संग 195.4 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3166.99 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5200 रुपये के भाव पर खूलकर, 5200 रुपये के दिन के उच्च और 5060 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 85 रुपये या 1.63 फीसदी गिरकर 5125 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 87 रुपये या 1.67 फीसदी गिरकर 5123 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 312.2 रुपये के भाव पर खूलकर, 317.4 रुपये के दिन के उच्च और 308.6 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 306.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 8.8 रुपये या 2.87 फीसदी की मजबूती के साथ 315.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 8.8 रुपये या 2.87 फीसदी की तेजी के संग 315.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 1004 रुपये पर खूलकर, 14.7 रुपये या 1.45 फीसदी औंधकर 1001 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11735.48 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 21204.89 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4046.49 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 520.52 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 259.89 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 383.23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1074.09 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2080.61 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.50 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19361 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 74097 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28229 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 418166 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 46872 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16229 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 39985 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 102333 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22359 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 46848 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 36630 पॉइंट पर खूलकर, 36650 के उच्च और 36260 के नीचले स्तर को छूकर, 454 पॉइंट घटकर 36260 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 46 रुपये की गिरावट के साथ 115.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.1 रुपये की बढ़त के साथ 22.95 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 144000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 183 रुपये की गिरावट के साथ 710.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2370.5 रुपये की गिरावट के साथ 12815.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 15.39 रुपये की गिरावट के साथ 28.67 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4 रुपये की गिरावट के साथ 9.5 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 43.1 रुपये की बढ़त के साथ 97.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.25 रुपये की गिरावट के साथ 17.5 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 72.5 रुपये की बढ़त के साथ 368 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1922 रुपये की बढ़त के साथ 12750 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2 पैसे के सुधार के साथ 31.57 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 60 पैसे की नरमी के साथ 2.87 रुपये हुआ।

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

अटूट आस्था के 1000 वर्ष

"वर्ष 2026, सोमनाथ में हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने का वर्ष है। बार-बार हुए आक्रमणों के बावजूद, सोमनाथ आज भी गर्व के साथ अडिग खड़ा है।"

– माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

उत्सव के मुख्य आकर्षण :

72 घंटों का अखंड ओमकार | देश के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भक्ति संगीत | सोमनाथ गाथा ड्रोन शो | शंखनाद महाआरती

8 से 11 जनवरी, 2026 | स्थान : श्री सोमनाथ मंदिर परिसर, प्रभास पाटन

"सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विध्वंस पर सृजन की शाश्वत और सनातन विजय का गर्जनाद है।"
– श्री हर्ष संघवी
(उप मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार)